रोजगार के अवसर सरकार की प्राथमिकता

यूपी का बजट पेश : कृषि योजनाओं पर जोर 10,888 करोड़ रुपए का प्रावधान

लखनऊ, 11 फरवरी. योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों का सशक्तिकरण, रोजगार के अवसर सृजित करना सरकार की प्राथमिकता है.

सरकार ने अपनी बात को सार्थक करते हुए बजट में कृषि योजनाओं पर जोर दिया। इस बजट में कृषि योजनाओं के लिये 10,888 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

बजट में पशुधन, मत्स्य, खाद्य-रसद, उद्यान विभाग के लिए भी बजट में बड़ी धनराशि की व्यवस्था की है। यूपीएग्रीज परियोजना के अन्तर्गत एग्रीएक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिये 245 करोड़ रुपये सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बजट 2026-27 में कृषि योजनाओं के लिये लगभग 10,888 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, यह वर्ष 2025-2026 के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है। खन्ना ने बताया कि वर्ष 2026-2027 में 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन एवं 48.18 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य है।

> एक्राब्रिज द्वारा प्रस्तावित यूपीएग्रीज परियोजना में एक्रा कल्चर आधारभूत संरचना के तहत विश्वस्तरीय हैचरी तथा विश्वस्तरीय ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की बाह्य सहायतित परियोजना के लिये 155 करो? रुपये प्रस्तावित किए गए हैं.यूपीएग्रीज परियोजना के अन्तर्गत एग्रीएक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिये 245 करो? रुपये तथा किसान उत्पादक संगठनों हेतु रिवाल्विंग फण्ड योजना के लिये 75 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है.

चाइनीज मांझे की चपेट में आकर युवक गंभीर रूप से घायल

प्रयागराज, 11 फरवरी. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चाइनीज मंझे पर प्रतिबंध के शासनादेश के बावजूद प्रयागराज में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, जिससे लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। प्रयागराज में मंगलवार शाम को एक ऐसा ही मामला सामने आया, जब सिविल लाइंस इलाके में निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी महेंद्र सिंह चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी आंख के पास गहरी चोट आई है और सात टांके लगाने पड़े। महेंद्र सिंह कीडगंज थाना क्षेत्र के निवासी हैं। वह एक निजी फाइनेंस कंपनी में फील्ड ऑफिसर के पद पर तैनात हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के मंडल प्रभारी भी हैं.

सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं सरकार

एक्स पर पोस्ट करते हुए लगाए लापरवाही का आरोप

दिल्ली की अब जनता सुरक्षित नहीं : केजरीवाल

पूर्व सीएम ने कामकाज को लेकर उठाए सवाल

नई दिल्ली, 11 फरवरी. दिल्ली की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला है.

उन्होंने आरोप लगाया कि एक साल के भीतर राजधानी की स्थिति बिगड़ गई है और प्रशासन जनता की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार कब जागेगी और कब जवाबदेही तय होगी। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। विपक्ष इसे शासन-प्रशासन की विफलता बता रहा है, जबकि सत्तापक्ष की ओर से अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

दिल्ली में हाल के घटनाक्रमों, नागरिक सुविधाओं और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर पहले भी आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं, लेकिन केजरीवाल का यह बयान राजनीतिक माहौल को और तीखा बना गया है। सोशल मीडिया पर भी इस पोस्ट को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है, जहां समर्थक और विरोधी अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

एक नजर में

फिलीपींस में जहाज डूबने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हुई

फिलीपींस, 11 फरवरी. फिलीपींस के बेसिलन प्रांत के पास यात्री-मालवाहक जहाज त्रिशा कर्स्टिन 3 के डूबने से कम से कम 52 लोगों की मौत हो गयी है। फिलीपीन कोस्ट गार्ड (पीसीजी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पीसीजी ने तकनीकी गोताखोर टीमों के चल रहे प्रयासों का हवाला देते हुए बताया कि गोताखोरों ने मंगलवार तड़के बालुक-बालुक द्वीप के पास खोज और बचाव अभियान के दौरान एक और शव बरामद किया, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 52 हो गयी है। कुल मिलाकर 316 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि बचाव दल अभी भी शेष पीड़ितों की तलाश में जुटे हैं। यह जहाज 26 जनवरी की रात बेसिलन से लगभग एक समुद्री मील की दूरी पर डूब गया था, जिसमें 332 यात्री और चालक दल के 27 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने कहा कि डूबने का संभावित कारण तकनीकी खामी थी। कोस्ट गार्ड ने एक बयान में कहा, लगभग सुबह सात बजे, पीसीजी के तकनीकी गोताखोरों ने मलबे वाली जगह पर अभियान शुरू किया। पंद्रह मिनट बाद, गोताखोर टीम ने डूबे हुए जहाज से एक महिला का शव बरामद किया। शव को पीसीजी के जहाज बीआरपी मेलचोरा एक्विनो द्वारा निकाला गया. खोज और बचाव अभियान अभी भी जारी है, क्योंकि अधिकारी फेरी पर सवार सभी यात्रियों और चालक दल का पता लगाने में लगे हैं।

ब्रिक्स, एससीओ आम सहमति से काम करते हैं

मॉस्को, 11 फरवरी. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) ज्यादातर मामलों में सर्वसम्मति के आधार पर फैसले करते हैं, जबकि नाटो के फैसले अमेरिका पर निर्भर करते हैं। श्री लावरोव ने रूस के एक यूट्यूब चैनल एमपाशिया मनुची प्रोजेक्ट के साथ बातचीत में कहा, ज्यादातर मामलों में अंतरराष्ट्रीय समझौतों का पालन किया जाता है। जब बात हमारे पश्चिमी साथियों की हो तब नहीं, बल्कि जब उन प्रतिनिधियों की होती है जिन्हें हम वैश्विक बहुमत कहते हैं, (जैसे) ब्रिक्स, एससीओ, और सोवियत के बाद वाले सीएसटीओ, ईएईयू, और सीआईएस। इन ढांचों में आम सहमति ज्यादातर बनी रहती है। आप नाटो की तरह आसानी से फ़ैसले नहीं ले सकते, जहां अमेरिकी कहते हैं चुप रहो और ... हमें दिखता है कि यह सब कैसे काम करता है। श्री लावरोव ने कहा कि यूरोपीय संघ भी फैसलों पर असर डालता है। यूरोपीय संघ की तरह, जहां ब्रसेल्स में बिना चुने हुए नौकरशाह देश की चुनी हुई सरकारों को बताते हैं कि क्या करना है, कैसे बर्ताव करना है, किसके साथ व्यापार करना है और किसके साथ नहीं करना है। हमारे हंगरी के साथियों ने ब्रसेल्स के हाल के गलत कामों पर साफ और समझने लायक टिप्पणी की है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने दिसंबर 2025 में कहा था कि यूरोपीय संघ यूक्रेनी संघर्ष को लंबा खींचने के लिए व्यवस्थित तरीके से कानून को रौंद रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ में कानून का राज ब्रसेल्स की तानाशाही से बदल गया है।

ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बने मोदी : उच्चायुक्त

नई दिल्ली, 11 फरवरी . भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्तअनिल सूकलाल ने बुधवार को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर विकासशील देशों की चिंताओं को लगातार उठाने में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की सराहना की. उन्होंने विकासशील देशों के लिए किए जा रहे प्रयासों को अभूतपूर्व बताया. ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज पीएम मोदी बन गए है. सूकलाल ने कहा कि भारत लंबे समय से ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करता रहा है. उन्होंने कहा कि 2023 में भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर अफ्रीकी संघ को जी20 का स्थायी सदस्य बनाया गया. दक्षिण अफ्रीका समेत पूरे अफ्रीकी महाद्वीप ने इस कदम की सराहना की .उच्चायुक्त ने बताया कि भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट' की शुरुआत की, जिसकी अध्यक्षता दो बार पीएम मोदी ने की. इस पहल ने विकासशील देशों के प्रमुख मुद्दों को वैश्विक एजेंडा में प्रमुखता से रखा और साझा समाधान पर जोर दिया. सूकलाल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले दस वर्षों में भारत की जीडीपी दोगुनी से अधिक हुई है और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है. उन्होंने ब्रिक्स, जी20 और ग्लोबल साउथ पहल में भारत की सक्रिय भूमिका को उभरती बहुध्रुवीय दुनिया को आकार देने वाला बताया. दक्षिण अफ्रीकी उच्चायुक्त ने बांग्लादेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार की वापसी की उम्मीद जताई. उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार द्वारा चुनाव कराने का फैसला स्वागतयोग्य है और शांतिपूर्ण चुनाव क्षेत्रीय व वैश्विक स्थिरता के लिए जरूरी हैं.

हाई-सीज ऑयल रैकेट की जांच में तीन जहाज रडार पर

नई दिल्ली, 11 फरवरी. भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने मुंबई तट से करीब 100 समुद्री मील दूर रोके गए तीन जहाजों के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू कर दी है। इन पर एक संगठित अंतरराष्ट्रीय तेल तस्करी नेटवर्क का हिस्सा होने का संदेह है। फिलहाल ये तीनों पोत मुंबई तट के पास लंगर डाले हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार, जांच में यह संकेत मिले हैं कि कम लागत वाले तेल और तेल-आधारित कार्गो को संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों से समुद्री मार्ग के जरिए गुप्त रूप से स्थानांतरित किया जा रहा था। समुद्री खुफिया आकलन बताते हैं कि जांच के दायरे में आए ये जहाज़ ईरान-संबंधित पेट्रोलियम व्यापार से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंधों की सूची में भी शामिल हैं.

अमेरिका की मिडिल-ईस्ट में बढ़ी तैनाती

नई दिल्ली, 12 फरवरी. मिडिल-ईस्ट में एक बार फिर भू-राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने कई अहम सैन्य ठिकानों पर तैनाती बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से खुलासा हुआ है कि कतर के अल-उदीद एयरबेस पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को स्थायी लॉन्चर से हटाकर ट्रकों पर रखा गया है। यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि रणनीतिक संकेत माना जा रहा है। इससे मिसाइलों को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर नई पोजिशन में तैनात किया जा सकता है।

जनवरी की तुलना में फरवरी में अमेरिकी विमानों, टैंकरों और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की संख्या भी कई बेसों पर बढ़ी नजर आई है। जॉर्डन, सऊदी अरब, ओमान और हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया तक यह गतिविधि फैली हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ईरान पर सैन्य दबाव बनाने के साथ-साथ संभावित हमले की तैयारी का संकेत भी देता है, जबकि दूसरी ओर दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट और फोरेंसिक इमेजरी विश्लेषण से सामने आया है कि फरवरी की शुरुआत में कतर के अल-उदीद एयरबेस पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम एचईएमटीटी ट्रकों पर तैनात दिखा। विश्लेषक विलियम गुडहाइंड के अनुसार, यह बदलाव मिसाइलों को अधिक मोबाइल और सुरक्षित बनाता है,नई जगह पर ले जाया जा सके। 1 फरवरी की तस्वीरों में यहां एक आरसी-135 रीकॉनिसेंस विमान, तीन ष्ट-130 हरक्यूलिस, 18 के सी -135 स्ट्रैटो टैंकर और सात सी -17 विमान दिखाई दिए.

विमान सेवा कंपनी इंडिगो को दी गई विशेष रियायत समाप्त

पायलट के लिए विशेष नियम 30 अप्रैल स्थगित

नई दिल्ली, 11 फरवरी. निजी विमान सेवा कंपनी इंडिगो को दिसंबर के पहले सप्ताह में परिचालन में भारी व्यवधान के बाद दी गयी विशेष रियायत बुधवार को समाप्त हो गई.

हालांकि सभी विमान सेवा कंपनियों के लिए पायलट के अनिवार्य आराम संबंधी नये नियम 30 अप्रैल तक स्थगित रहेंगे। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने आज एक नोट में बताया कि इंडिगो के विशेष अनुरोध पर 05 दिसंबर को फ्लाइट ड्यूटी संबंधी नियमों के दो प्रावधानों में छूट दी गयी थी.

इस दौरान इंडिगो के लिए नाइट ड्यूटी की परिभाषा रात 12 बजे से सुबह पांच बजे तक कर दी गयी थी जबकि नये नियमों में नाइट ड्यूटी रात 12 बजे से सुबह छह बजे तक है। इसके अलावा नियम यह है कि नाइट ड्यूटी से इतर शुरू होने वाली ड्यूटी जो नाइट ड्यूटी तक जारी रहती है, उसमें पायलट के फ्लाइट का अधिकतम समय आठ घंटे और ड्यूटी का अधिकतम समय 10 घंटे हो सकता है। इस दौरान पायलट अधिकतम दो लैंडिंग करा सकता है. इंडिगो को इस नियम से भी छूट दी गयी थी। नियामक ने बताया कि इस दौरान इंडिगो के परिचालन की नजदीकी निगरानी की गयी। एयरलाइंस ने डीजीसीए को सूचित किया है कि वह इन छूटों को समाप्त होने के बाद भी 11 फरवरी से सुचारू परिचालन के लिए तैयार है।

> इसके अलावा जिन नियमों को 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया है उनमें पायलट के लिए किसी भी 24 घंटे में अधिकतम फ्लाइट समय और लैंडिंग की सीमा संबंधी नियम शामिल है। एक अन्य प्रावधान पायलट के आराम के घंटों से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि जितने घंटे की ड्यूटी है उसके बाद उतने ही घंटे का आराम मिलना चाहिये कम से कम 12 घंटे का आराम देना होगा। यदि पायलट ने तीन से सात टाइम जोन पार किये हैं तो कम से कम 18 घंटे और सात से अधिक टाइम जोन पार करने पर कम से कम 36 घंटे का आराम मिलना चाहिये। अनिवार्य 48 घंटे के साप्ताहिक अवकाश संबंधी नियम भी 30 अप्रैल तक स्थगित रहेंगे.

निवेशकों को निवेश का दिया न्योता

नई दिल्ली, 11 फरवरी. ओमान अपने प्लास्टिक क्लस्टर की सफलता को दोहराने की कोशिश के तहत भारतीय निवेशकों को नयी योजना वाले एल्युमीनियम प्रोसेसिंग ज़ोन में हिस्सा लेने के लिये आमंत्रित कर रहा है.

इससे यह पहल तेज़ी से बढ़ रही भारत-ओमान आर्थिक साझेदारी के तहत आयेगी। लादायन कार्यक्रम के प्रमुख मुंधर अल-रवाहि ने यूनीवार्ता से बातचीत में कहा कि ओमान एल्युमिनियम क्षेत्र के इर्द-गिर्द एक संपूर्ण इकोसिस्टम विकसित करना चाहता है। उनका कहना है कि यह नया औद्योगिक क्लस्टर कच्चे माल के निर्यात के बजाय मूल्य वर्धित प्रसंस्करण और विनिर्माण पर केंद्रित होगा। तीन वर्ष पहले ओमान ने प्लास्टिक विकास ज़ोन की शुरुआत की थी, जिसमें अब तक 28 परियोजनाओं पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

इनमें से करीब 10 परियोजनाओं में उत्पादन शुरू कर चुका है या शुरू होने के करीब हैं, जबकि शेष विभिन्न चरणों में हैं। श्री अल-रवाहि ने कहा- इसी मॉडल को अब एल्युमिनियम क्षेत्र में लागू करने की योजना है-जिसमें देश के स्मेल्टर्स को निचली श्रेणी के उद्योगों के लिए मुख्य आपूर्तिकर्ता बनाया जाएगा। भारत-ओमान के बीच 2020 से अब तक निवेश प्रवाह तीन गुना बढ़कर पांच अरब डॉलर तक पहुंच गया है। धातु विनिर्माण ,हरित इस्पात और अमोनिया जैसे क्षेत्र सहयोग के प्रमुख स्तंभ बनकर उभरे हैं।

आज का इतिहास

1742 – महान मराठा दिग्गज नाना फडनवीस का जन्म।
1809 – ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्म।
1809– अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जन्म।
1818– चिली ने स्पेन से आजादी की औपचारिक घोषणा की।
1824– आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म।
1920– खलनायक की भूमिका के लिए मशहूर रहे बॉलीवुड एक्टर प्राण का जन्म।
1922– चौरी-चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म करने की घोषणा की।

दिल्ली में 10 लाख की रिश्वत लेते एएसआई गिरफ्तार

प्रॉपर्टी विवाद सुलझाने के नाम पर मांगी थी रिश्वत

नई दिल्ली, 11 फरवरी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली पुलिस के सीआर पार्क थाने में तैनात एक सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) को कथित रूप से 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी पर प्रॉपर्टी विवाद सुलझाने और शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई न करने के बदले यह रकम मांगने का आरोप है.

सीबीआई ने मंगलवार को आरोपी एएसआई सुंदर पाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था. एजेंसी के अनुसार, आरोपी ने शिकायतकर्ता से प्रॉपर्टी विवाद निपटाने के नाम पर 25 लाख रुपये की मांग की थी और आश्वासन दिया था कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी.

सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी को 25 लाख रुपये की कथित रिश्वत में से 10 लाख रुपये की आंशिक रकम मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. सीबीआई के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि भ्रष्ट लोकसेवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई एजेंसी की भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या रिश्वत की मांग का सामना करना पड़े तो इसकी

यूथ कनेक्ट और संस्कृति पर ब्रिक्स में बनी सहमति

- **अकादमिक, थिंक टैंक, बिजनेस फोरम पर प्रस्तुतियां**
- **ब्रिक्स 2026 : भारत के नेतृत्व में नई पहल**

नई दिल्ली, 11 फरवरी. भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स 2026 की तैयारियों ने ठोस रूप लेना शुरू कर दिया है.

नई दिल्ली में 9-10 फरवरी को में आयोजित शेरपा और सूस शेरपा की दो दिवसीय बैठक में सदस्य देशों ने सालभर के एजेंडे, प्राथमिकताओं और बैठकों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की.

प्रधानमंत्री के 'जन-केंद्रित' और 'मानवता-प्रथम' दृष्टिकोण को आधार बनाते हुए भारत ने स्वास्थ्य, जलवायु, ऊर्जा, नवाचार, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में साझा पहलों का खाका पेश किया.

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने ब्रिक्स 2026 की थीम, लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। बैठक में ब्राजील, चीन, रूस, साउथ अफ्रीका के साथ नए सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। यह बैठक इस बात का संकेत है कि भारत ब्रिक्स मंच को अधिक समावेशी, परिणामोन्मुख और जन-हितैषी दिशा में आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, बैठक की अध्यक्षता भारत के ब्रिक्स शेरपा और आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने की.

> जबकि सूस शेरपा के रूप में संयुक्त सचिव शंभू एल. हक्की ने सहयोग किया। 10 फरवरी को प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाकात कर आगे की प्राथमिकताओं पर विचार साझा किए। इस दौरान लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण थीम के तहत भारत ने बहुआयामी एजेंडा रखा। बैठक में स्वास्थ्य, कृषि, श्रम एवं रोजगार, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आईसीटी, नवाचार, सुरक्षा और आतंक-रोधी सहयोग जैसे विषयों पर मंत्रालयों ने प्रस्तुतियां दीं.

कार्यक्रम मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का किया शुभारंभ

महिलाओं के संघर्ष, साहस को मिलेगी नई दिशा

देहरादून, 11 फरवरी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया.

मुख्यमंत्री ने योजना का शुभारंभ करते हुए प्रथम चरण में जनपद बागेश्वर (42 लाभार्थी), देहरादून (191), नैनीताल (75), पौड़ी (66), टिहरी (23) एवं उधमसिंहनगर (87) के कुल 484 लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में ?3 करोड़ 45 लाख 34,500 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में भेजी। इसके साथ मुख्यमंत्री ने विभागीय कैलेंडर का भी विमोचन किया.

> **महिलाओं के बिना समाज की उन्नति संभव नहीं**
> मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और उन्हें सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। की लाखों महिलाओं के संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास को नई दिशा दी जा रही है। महिलाओं के बिना किसी भी राष्ट्र और समाज की उन्नति संभव नहीं है .महिला के सशक्त होने से परिवार के साथ पूरा समाज सशक्त होता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत कुल 484 लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में 3 करोड़ 45 लाख 34,500 की धनराशि दी जा रही है। शेष 7 जनपदों की 540 महिलाओं को भी लगभग 4 करोड़, महीने के अंत तक डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे.

हत्या के मामले में 12 व्यक्तियों को मौत की सजा

कोलंबो, 11 फरवरी. श्रीलंका की गम्पाहा हाईकोर्ट ने बुधवार को वर्ष 2022 में तत्कालीन सांसद अमरकीर्ति अथुकोराला और उनके सुरक्षा अधिकारी की हत्या के मामले में 12 व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। यह फैसला एक लंबी सुनवाई के बाद आया है, जिसमें इन हत्याओं के संबंध में कुल 42 लोगों को आरोपित किया गया था। अदालत ने चार अन्य व्यक्तियों को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। अन्य 23 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार, मई 2022 में देशव्यापी अशांति के दौरान सांसद और उनके सुरक्षा अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों की एक आक्रोशित भीड़ पर उस समय गोलियां चला दी थीं.

बेबुनियाद आरोप लगाना राहुल गांधी की आदत : हरदीप

नई दिल्ली, 11 फरवरी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एपस्टीन फाइल के संदर्भ में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुये बुधवार को विस्तार से सफाई दी और कहा कि उनका नाम इस मामले में गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है.

श्री पुरी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस मामले में अनावश्यक विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बेबुनियाद आरोप लगाना श्री गांधी की आदत हो गयी है। उनकी राजनीतिक बयानबाजी में मनोरंजन का तत्व अधिक दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि एपस्टीन फाइल से जुड़े कई दस्तावेज पहले से सार्वजनिक डोमेन में मौजूद हैं और लगभग 30 लाख ई-मेल जारी हुए हैं। श्री पुरी ने स्पष्ट किया कि मई 2009 से लेकर आठ वर्षों तक वह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत रहे और वर्ष 2017 में मंत्री बने।

इस अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और कार्यक्रमों में कई वैश्विक व्यक्तियों से उनकी मुलाकातें हुईं, जिनमें एप्सटिन से तीन-चार मुलाकातें भी शामिल थीं। श्री पुरी ने कहा कि विदेश सेवा से सेवानिवृत्ति के कुछ समय बाद उन्हें इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट (आईपीआई) से जुड़ने का निमंत्रण मिला था, हालांकि वह संस्था का नियमित हिस्सा नहीं थे। इसके कार्यक्रमों के दौरान या प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में एपस्टीन से मुलाकात हुई.

और ये सब इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े कार्यक्रमों का हिस्सा भर था। केन्द्रीय मंत्री ने कहा उस समय उनका प्राथमिक संपर्क लिंकडइन के सह-संस्थापक रीड हॉफमैन से था और उन्होंने इंटरनेट उद्यमी को भारत आने का निमंत्रण दिया था। इसके साथ ही श्री पुरी ने कहा कि एप्सटीन के आईलैंड से उनका कोई लेना-देना नहीं है.